



# झारखण्ड गजट

## असाधारण अंक

### झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

---

4 आषाढ़, 1941 (श०)

संख्या- 519 राँची, मंगलवार,

25 जून, 2019 (ई०)

---

#### कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

-----  
आदेश

18 जून, 2019

आदेश संख्या:-5/आरोप-1-53/2015 का.- 4783-- श्री देवेन्द्र भूषण सिंह, झा०प्र०से० (कोटि क्रमांक-471/03), तत्कालीन उप विकास आयुक्त, खूँटी को नाबालिग लड़की के साथ लैंगिक उत्पीड़न करने के आरोप में विभागीय आदेश सं०-7307, दिनांक 13.08.2015 द्वारा तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है तथा इनका मुख्यालय प्रमंडलीय आयुक्त का कार्यालय, दक्षिणी छोटानागपुर प्रमंडल, राँची निर्धारित किया गया।

2. उपायुक्त, खूँटी के पत्रांक-1315/गो०, दिनांक 26.12.2017 द्वारा समर्पित प्रतिवेदन के समीक्षोपरांत विभागीय अधिसूचना सं०-90(HRMS), दिनांक 30.01.2018 द्वारा श्री सिंह को तत्काल प्रभाव से निलम्बन से मुक्त किया गया।

3. श्री सिंह के पत्रांक-801, दिनांक 11.03.2019 द्वारा माननीय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम, खूँटी द्वारा दिनांक 01.03.2019 को पारित न्यायादेश की प्रति उपलब्ध कराते हुए निलंबन अवधि को विनियमित करने का अनुरोध किया गया, जिसके आलोक में उपायुक्त, खूँटी से विभागीय पत्रांक-3321, दिनांक 25.04.2019 एवं पत्रांक-3812, दिनांक 17.05.2019 द्वारा उक्त पारित न्यायादेश की सत्यापित प्रति एवं वाद की अद्यतन स्थिति उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया।

4. उपायुक्त, खूँटी के पत्रांक-594/वि०, दिनांक-28.05.2019 द्वारा खूँटी थाना कांड सं०-121/15, जी०आर० वाद सं०-358/15, पोक्सो वाद सं०-10/17 में माननीय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम, खूँटी द्वारा दिनांक 01.03.2019 को पारित न्यायादेश की सत्यापित प्रति उपलब्ध करायी गयी है, जिसमें इस वाद के अभियुक्त श्री देवेन्द्र भूषण सिंह को भारतीय दण्ड विधान की धारा 354ए, 354बी, 509 धारा-3(1)(xi)(xii) एस०सी०/एस०टी० एक्ट तथा 12 पोक्सो एक्ट के अन्तर्गत लगाये गये सभी आरोपों के लिए निर्दोष मानते हुए इन्हें बाईज्जत रिहा किया गया है।

5. श्री सिंह से प्राप्त आवेदन एवं जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम, खूँटी द्वारा पारित न्यायादेश के आलोक में इनके दिनांक 13.08.2015 से 29.01.2018 तक की निलंबन अवधि को झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-11 के अन्तर्गत पूर्ण वेतन एवं भत्ते पर कर्तव्य पर बिताई गई अवधि के रूप में विनियमित किया जाता है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

**अशोक कुमार खेतान,**  
सरकार के संयुक्त सचिव।

-----